बजट भाषण

2022—2023

[भाग–क]

माननीय अध्यक्ष जी,

1. मुझे इस सम्मानित सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। यह इस सरकार का लगातार आठवां बजट है।

2. माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में तैयार किए गए और इस सदन द्वारा पास किए गए पिछले सात बजट की बदौलत आज दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे-ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं जिनसे आज देश के कई राज्यों की सरकारें प्रेरणा ले रही हैं. स्कूल बने हैं. नए विश्विद्यालय बने हैं. अस्पताल बने हैं. मोहल्ला क्लिनिक बने हैं. दिल्ली की जनता को 24 घंटे बिजली मिल रही है. करीब 75% घरों में बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं. दिल्ली मेट्रो और बसों का विस्तार हुआ है. सड़कों और मेट्रोलाइन का नेटवर्क बढ़ा है. दिल्ली की गली गली में सीसीटीवी कैमरे लगाकर अपराध रोकने और महिला सुरक्षा की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाये गए हैं. युवाओं के लिए फ्री-वाई फाई नेटवर्क लगाए गए हैं. अंतराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं विकसित की गई हैं.

3. इतना ही नहीं, सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी जैसी अभूतपूर्व सुविधा की शुरुआत की गई जिसमें लोग सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटते बल्कि सरकारी दफ्तर का आदमी लोगों के घर के चक्कर काटता है. सरकारी दफ्तर में जिस काम के लिए आम आदमी को धक्के खाने पड़ते थे, कोई दलाल ढूंढना पड़ता था और उसको रिश्वत देकर काम कराना पड़ता था आज वह काम सिर्फ एक फोन करने पर घर बैठे हो रहा है. यह करिश्मा भी दिल्लीवासियों ने पिछले सात साल में देखा है.

4. इस सदन में अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए पिछले सात बजट के सफल क्रियान्वयन के चलते पिछले सात साल में दिल्ली सरकार ने विभिन्न विभागों और संस्थानों में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरियां दी गई हैं. इनमें से 51,307 नौकरियां तो पक्की सरकारी नौकरियां हैं जो पिछले 7 साल में DSSSB द्वारा परीक्षा ले कर दी गई है. यहां यह भी जानना जरूरी होगा कि हमसे पहले की सरकारों में करीब 9 साल तक ना के बराबर नौकरी दी गई थी। उन्होंने सरकारी नौकरियां के लिए परीक्षा तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करके रखा हुआ था. मुझे याद हैं कि जब 2013-14 में 49 दिन के लिए केजरीवाल जी की सरकार बनी थी तो मैंने उस समय के DSSSB के अधिकारियों के साथ लगातार 1 सप्ताह तक मीटिंग करके इन नौकरियों को तुरंत भरने का प्लान बनाने को कहा था. अपनी उस वक्त की क्षमता के साथ वे मेरे सामने एक प्लान लेकर आए थे. मैंने उनसे पूछा था कि , उनके उस प्लान के मुताबिक, सारी पेंडिंग वैकेंसीज कितने समय में भर जाएंगे? उन्होंने खुद माना था कि उस स्पीड से तो मौजूदा वैकेंसीज को भरने में ही 38 साल लग जाएंगे जबकि इस बीच लाखों नई वैकेंसीज और क्रिएट हो जाएंगी। बहरहाल, उस दौरान जो भी जरूरी था वह तमाम संसाधन उनको उपलब्ध कराए गए और पूरा बैकलॉग क्लियर करने के लिए कहा गया. उसके बाद से DSSSB ने अपने काम की स्पीड पकड़ी तो सात साल में 51,307 युवाओं को नई नौकरियां दी जा चुकी है. इन 51,307 पक्की सरकारी नौकरियों के साथ-साथ दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज़ में करीब 2,500 पक्की नौकरियां दी गई हैं। अस्पतालों में भी करीब 3,000 पक्की नौकरियां दी गई है. सात साल के दौरान करीब 25,000 नए युवा टीचर्स को गेस्ट टीचर्स के रूप में रखा गया है. इसी तरह करीब 50 हजार नौकरियां

सैनिटेशन और सिक्योरिटी के लिए रखी गई एजेंसीज के माध्यम से दी गई है. मात्र सात साल में दिल्ली में 1,78,000 युवाओं को, नई नौकरियां सरकार में मिलना कोई छोटी बात नहीं है।

5. रोजगार डेटा केवल सरकारी नौकरियों का और उससे जुड़े संस्थानों में सरकारी नौकरियों की बात है। पिछले सात साल में, 24 घंटे बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाओं में सुधार, ईमानदार सरकार, जीरो टैक्स पालिसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधाएं देकर दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर खासकर लघु और मध्यम व्यवसाय के फलने-फूलने का जो माहौल बना है उसने प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में भी भारी बढ़ोत्तरी की है। दिल्ली रोजगार पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख रोजगार तो केवल कोविड के बाद के समय में ही देखने को मिले।

6. अध्यक्ष महोदय पिछले सात वर्षों में इस सदन में प्रस्तुत बजट प्रस्तावों और योजनाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई. और यही वजह है कि सात साल में शिक्षा और स्वास्थ्य में हुए दूरदर्शी निवेश के कारण कोविड महामारी के बीच भी, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इसीलिए संभल पाई, क्योंकि पिछले सात वर्षों में यहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर निवेश किया गया था. अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सें, सपोर्ट स्टाफ, नए बेड्स, वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों की कमी इसीलिए नहीं हुई क्योंकि कोविड के पहले के पांच वर्षों में इस सदन में जो पांच बजट प्रस्तुत किए गए उन सब में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बहुत समझदारी से और प्राथमिकता के आधार पर निवेश किया गया था.

7. कोविड-19 महामारी से तो हम निपट लिए लेकिन हम सब वाकिफ हैं कि, पूरे देश में भी और दिल्ली में भी, बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार और व्यापार को भारी नुकसान हुआ है. तत्काल राहत के लिए पिछले दो वर्षों में पीड़ित और जरूरतमंद परिवारों और लोगों को वित्तीय सहायता, अनुदान राशि, राशन, भोजन आदि की व्यवस्था कर कुछ फौरी मदद की गई है लेकिन फौरी मदद तो फौरी मदद होती है. लोगों को रोज़गार चाहिए.

8. इस सदन में अपने आठवें बजट में मैं दिल्ली वासियों के लिए नए रोजगार सृजित करने और अर्थव्यवस्था को कोविड, जीएसटी, नोटबंदी जैसे तमाम कारणों से पिछले वर्षों में हुए नुकसान से उबारने का एक एजेंडा प्रस्तुत कर रहा हूं. इससे व्यापार उद्योग व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे दिल्ली के नागरिकों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा होंगे. इस बजट में प्रस्तुत योजनाओं एवं प्रस्तावों से न केवल दिल्ली के युवाओं को उद्यमशीलता के नए अवसर मिलेंगे बल्कि पहले से स्थापित उद्यम और व्यापार भी लाभान्वित और समृद्ध होंगे.

9. मैंने विगत सात वर्षों में इस सदन में सरकार की प्राथमिकता के आधार पर जीरो टैक्स बजट प्रस्तुत किया है, एजुकेशन बजट प्रस्तुत किया है, हेल्थ बजट प्रस्तुत किया है, ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है, देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया है. आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में आगामी वित्त वर्ष के लिए "रोज़गार बजट' प्रस्तुत कर रहा हूं.

10. मैंने पिछले वित्त वर्ष के देशभक्ति बजट में, आजादी के 75 वर्ष में, इस सदन के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से यह संकल्प प्रस्तुत किया था कि हमें दिल्ली की

अर्थव्यवस्था को बहुत समझदारी और दूरदर्शिता से उस तरफ लेकर जाना है कि भारत जब आजादी की 100 वीं वर्षगांठ मना रहा हो तो भारत की राजधानी के लोगों की पर कैपिटा इनकम उस वक्त की सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए. इस मुश्किल लेकिन संभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ योजनाएं मैंने पिछले बजट में प्रस्तुत की थी। 2047 तक दिल्ली वालों की आय को सिंगापुर वालों की उस वक्त की आय के बराबर ले जाने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे अधिक से अधिक दिल्लीवासियों के पास एक सम्मानजनक रोजगार हो. इसलिए इस बजट में, और 2047 के लिए देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष 'रोज़गार बजट' लेकर आया हूं. इन योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजार और व्यपार की रौनक और गरिमा को लौटा कर लाएंगे बल्कि, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को दिल्ली में प्रोत्साहन देंगे. इन सब प्रयासों से अगले पांच साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी.

11. 'रोज़गार बजट' के माध्यम से हमारा लक्ष्य आर्थिक विकास के इंजन को फिर से स्टार्ट करना और सुदृढ़ बनाना है. लेकिन अध्यक्ष महोदय 20 लाख नई नौकरियां वाले इस रोज़गार बजट के प्रस्ताव और योजनाओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले थोड़ी सी चर्चा मैं दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर रखना चाहूंगा.

दिल्ली का आर्थिक परिदृश्य

12. कोविड की पांच लहरों के बीच आई आर्थिक चुनौतियों से अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे उभर रही है और इसके चलते दिल्ली का GSDP प्रचलित बाजार मूल्यों पर वर्ष 2020-21 के 7,85,342 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 9,23,967 करोड़ रूपए रहने की संभावना है। यह 17.65 प्रतिशत वृद्धि का संकेत है।

13. मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्ष 2021-22 में दिल्ली की GSDP की वास्तविक वृद्धि दर 10.23 प्रतिशत रहने की संभावना है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि दर 8.9 प्रतिशत रहने का आकलन है। इसका अर्थ है कि हम महामारी पूर्व आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर पुन: पहुंच रहे हैं।

14. राष्ट्रीय स्तर पर GDP में दिल्ली के वास्तविक GSDP का योगदान 2011-12 में 3.94 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 4.21 प्रतिशत हो गया है। जबकि दिल्ली देश की कुल आवादी का केवल 1.52 प्रतिशत है। मैं यह बताना चाहूंगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मुख्यत: सेवा क्षेत्र का योगदान है और प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में इसका योगदान 83.94 प्रतिशत है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 13.78 प्रतिशत और प्राथमिक क्षेत्र का 2.28 प्रतिशत है।

15. वित्त वर्ष 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति-व्यक्ति आय बढ़कर 4,01,982 रुपए हो जाने की संभावना है। वर्ष 2020-21 में यह 3,44,136 रुपए

थी। यह 2021-22 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 16.81 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है।

16. वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत 1,49,848 रुपये से लगभग 2.7 गुणा अधिक है।

17. वर्ष 2020-21 के दौरान दिल्ली के GSDP में प्रचलित मूल्यों पर 1.09 प्रतिशत और वास्तविक मूल्यों पर 3.86 प्रतिशत का संकुचन कोविड-19 महामारी और इसके नियंत्रण के लिए किए गए प्रतिबद्ध उपायों का असर दर्शाते हैं। हालांकि अग्रिम अनुमानों का संकेत है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर 17.65 प्रतिशत और स्थिर मूल्यों पर 10. 23 प्रतिशत की वृद्धि रहेगी।

संशोधित अनुमान 2021-22

18. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 69,000 करोड़ रुपए के अनुमोदित बजट अनुमान की तुलना में संशोधित बजट अनुमान, 67,000 करोड़ रुपए का है। 67,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावित संशोधित अनुमान 2020-21 में 52,468 करोड़ रुपए के वास्तविक व्यय से 27.70 प्रतिशत अधिक है। संशोधित अनुमान राशि 67,000 करोड़ रूपये में राजस्व व्यय के लिए 50,862 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के लिए 16,138 करोड़ रुपए शामिल हैं। पूंजीगत बजट 2021-22 के लिए अनुमोदित बजट अनुमान के 17,201 करोड़ रुपए से कम होकर संशोधित अनुमान 2021-22 में 16,138 करोड़ रुपए हो गया है, यह मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के बाद पूंजीगत कार्यों की धीमी गति के कारण है।

19. स्थापना व्यय और अन्य प्रतिबद्ध देयताओं के लिए 2021-22 के अनुमोदित बजट अनुमान 31,200 करोड़ रुपए से बढ़कर संशोधित अनुमान में 32,400 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव है, ऐसा मुख्य रूप से कोविड-19 नियंत्रण संबंधी व्यय के कारण है। स्कीम/परियोजनाओं के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में 34,600 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अनुमोदित बजट अनुमान में यह 37,800 करोड़ रुपए था।

वर्ष 2021-22 के लिए पूरक अनुदान मांगे

20. महोदय, वर्ष 2021-22 के दौरान संशोधित अनुमानों में 468.22 करोड़ रुपए की पूरक अनुदान मांग की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं, पूरक अनुदान मांगों के लिए सदन का अनुमोदन चाहता हूं।

21. अब मैं अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं –

बजट अनुमान 2022-23

22. हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का कुल व्यय 2014-15 के दौरान 30,940 करोड़ रुपए था। मैंने जून 2015 में 41,129 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के साथ अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया था

23. अत्यंत हर्ष के साथ मैं वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं, जो वर्ष 2014-15 के 30,940 करोड़ रुपए व्यय की तुलना में लगभग ढाई गुणा है।

24. 75,800 करोड़ रुपए के बजट में 32,200 करोड़ रुपए स्थापना और अन्य प्रतिबद्ध व्यय के लिए और 43,600 करोड़ रुपए योजनाओं / कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए हैं। 75,800 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में 2022-23 में राजस्व के तहत 53,687 करोड़ रुपए और पूंजीगत परिव्यय के तहत 22,113 करोड़ रुपए शामिल हैं। 2021-22 के बजट अनुमान के खर्च में 17,201 करोड़ रुपए पूंजीगत मद के तहत और 51,799 करोड़ रुपए राजस्व के अतर्गत था। वर्ष 2021-22 की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में, पूंजीगत बजट में 29 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जबकि राजस्व व्यय में केवल 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा 2022-23 में प्रस्तावित पूंजीगत परिव्यय 22,113 करोड़ रुपए है जो वर्ष 2014-15 के 7,430 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय से लगभग तिगुना है।

25. वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित बजट अनुमान 75,800 करोड़ रुपए, वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 69,000 करोड़ रुपए से 9.86 प्रतिशत और संशोधित अनुमान से 13.13 प्रतिशत अधिक है।

26. वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट का वित्त पोषण 47,700 करोड़ रुपए कर राजस्व से, 1,000 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व से, 325 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से, 10,000 करोड़ रुपए लघु बचत

ऋण से, 802 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियों से, 10,000 करोड़ रुपए जीएसटी प्रतिपूर्ति से, 1,621 करोड़ रुपए केंद्र प्रायोजित योजनाओं से और केवल 643 करोड़ रुपए भारत सरकार की अनुदान सहायता से और बाकी प्रारंभिक शेष (ओपनिंग बैलेंस) से जुटायी जाएगी।

स्थानीय निकायों को वित्तीय सहयोग

27. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्थानीय निकायों को 4,374 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी। इसमें से 2,305 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबद्ध राशि के रूप में होंगे और 2,069 करोड़ रुपए बेसिक टैक्स असाइंमेंट (बीटीए) के रूप में होंगे।

28. इसके अलावा 1,780 करोड़ रुपए की राशि स्थानीय निकायों को स्टैंप और पंजीकरण शुल्क में हिस्से और एकमुश्त पार्किंग शुल्क के रूप में उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार हमारी सरकार बजट अनुमान 2022-23 में स्थानीय निकायों को 6,154 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय सहयोग दे रही है।

रोजगार बजट

29. अध्यक्ष महोदय अब मैं आपके समक्ष अपने 20 लाख नई नौकरियों वाले 'रोजगार बजट' के महत्वपूर्ण खंड को प्रस्तुत करना चाहता हूं. इसमें मैं दिल्ली की अर्थव्यवस्था को तरक्की के रास्ते पर ले जाने और इस तरक्की से रोजगार के लाखों अवसर पैदा होने की योजनाओं को रखूंगा।

30. अर्थव्यवस्था चाहे दिल्ली की हो या पूरे देश की, उसकी तरक्की का रास्ता अधिक से अधिक लोगों के हाथ में रोजगार होने से ही खुलता है. अगर दिल्ली के आंकड़ों को देखें तो हम पाते हैं कि दिल्ली की एक करोड़ 68 लाख की आबादी में से केवल 55 लाख 87 हजार लोगों के पास ही कोई रोजगार है. अर्थात दिल्ली में हमारी मात्र एक तिहाई आबादी के हाथ में ही कोई रोज़गार है. और इस तरह हमारी एक तिहाई आबादी के कंधों पर बाकी की दो-तिहाई आबादी की जिंदगी भी चलाने की जिम्मेदारी है।

31. दिल्ली के इन आंकड़ों की तुलना लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर जैसे शहरों से करते हैं तो हम पाते हैं कि लंदन की आबादी लगभग 90 लाख है, इसमें से 51 लाख, 60 हजार लोग रोजगार करते हैं. यानी कि लंदन में करीब 58% आबादी के पास रोजगार है. न्यूयोर्क की आबादी लगभग 88 लाख है, इसमें से 46 लाख 25 हजार लोगों के पास, यानी कि करीब 52.6% आबादी के पास रोजगार हैं। सिंगापुर की आज की आबादी करीब 55 लाख है और इसमें से 36 लाख 43 हजार लोगों के पास यानी कि करीब 67% लोगों के पास रोजगार हैं. अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का, पर कैपिटा इनकम को आगे बढ़ाने का रास्ता यहीं से समझ में आएगा।

32. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम दिल्ली की वर्किंग पापुलेशन का वर्तमान में 33% से बढ़ाकर अगले पांच साल में 45% तक ले जाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. यानी दिल्ली के कुल एक करोड़ 68 लाख लोगों की आबादी में से जो यह करीब 56 लाख लोग अभी कोई रोजगार करते हैं , इनकी संख्या बढ़ाकर हमें 76 लाख ले जानी होगी. इसका मतलब है कि अगले 5 साल में हमें

दिल्ली में 20 लाख नए जॉब क्रिएट करने होंगे. यह लक्ष्य कठिन है लेकिन केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में नामुमकिन नहीं है।

33. हमारी सरकार ने नए जॉब क्रिएट करने के लिए प्रमुखता से निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना है

a. रिटेल सेक्टर
b. फूड एंड बेवरेजिज
c. लोजिस्टिक एंड सप्लाई चेन
d. ट्रैवल और टूरिज्म
e. एंटरटेनमेंट
f. कंस्ट्रक्शन
g. रियल एस्टेट
h. ग्रीन एनर्जी

34. इन सभी सेक्टर्स में नई नौकरियां पैदा करने का एक ही तरीका है - दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर में और, बाजारों में मांग पैदा करना यानि की नई डिमांड पैदा करना. डिमांड बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था के कैरेक्टर को समझना होगा. भारत की अर्थव्यवस्था मूलतः अंतर्मुखी है. यानी अपनी खपत पर चलने वाली है. हमारी आबादी ही हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत है. भारत की जीडीपी का 60 फ़ीसदी हिस्सा आम लोगों के खर्च पर आधारित है. इसे और आम भाषा में समझें तो देश की अर्थव्यवस्था का 60% आम लोगों की कमाई और उनके द्वारा की जा रही खरीदारी यानी खपत से चलता है. अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है - खपत, खपत, खपत. आप अपने

नागरिकों की खपत करने की क्षमता बढ़ाइए, अर्थव्यवस्था अपने आप आगे बढ़ती चली जाएगी।दुनिया में मंदी के दौर से निकलने के लिए बार बार यह फार्मूला अपनाया गया है. दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने खुद को इसी रास्ते पर चलकर खड़ा कर लिया. 1945 के बाद अमेरिका में राजनेता, कारोबारी, श्रमिक नेता, कोई भी हो, सभी, देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित कर रहे थे. क्योंकि तेज विकास में इसी खर्च का असर दिख रहा था। 1945 से 1968 के बीच अमेरिका में मजदूरी 4 गुना बढ़ाई गई. दूसरे महायुद्ध के बाद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अमेरिका ने अपनी आबादी को अपनी ताकत बनाया।

35. आज भारत की युवा आबादी भारत की ताकत है. महामारी और महामंदी के प्रभाव से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमें अपनी इस युवा आबादी को रोजगार देने होंगे ताकि वह खर्च कर सके. युवाओं के हाथ में पैसा होगा तो वह खर्च करेगा। वह खर्च करेगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और उसके फल स्वरुप नए रोजगार बनेंगे। हमें केवल और केवल रोजगार बचा सकते हैं, बहुत से रोजगार ढेर सारे रोजगार ही हमें बचा सकते हैं. रोजगार विकास और समानता की गारंटी है. खपत के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार चाहिए। पीयू रिसर्च फाउंडेशन की रिसर्च बताती है कि भारत में कोविड-19 की लहर में ही 7.50 करोड़ लोग न्यू पुअर यानी नए निर्धन बने लोगों की कैटेगरी में आ गए थे. रिसर्च बताती है कि 2030 तक भारत में करीब 9 करोड़ नए रोजगार बनाने होंगे।

36. दिल्ली में हम इसकी एक आधारशिला रख रहे हैं. दिल्ली में अगले 5 साल में हम कम से कम 20 लाख नए रोजगार पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं. मैं इस बजट में कई योजनाएं प्रस्तावित कर रहा हूं जिनका लक्ष्य मेरे द्वारा अभी बयान की गई अपेक्षाओं को पूरा करना है. इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं-

i. दिल्ली के फेमस रिटेल मार्केट्स के लिए रिनोवेशन और इनोवेशन की योजनाएं।

ii. देश विदेश के ग्राहकों को दिल्ली में बुलाकर शॉपिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल।

iii. दिल्ली के होलसेल व्यापार का केंद्र होने के पुराने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल।

iv. दिल्ली के छोटे और स्थानीय बाजारों में स्थित दुकानदारों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए दिल्ली बाजार पोर्टल की शुरुआत,

v. गांधीनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े वस्त्र व्यापार केंद्र को दिल्ली गारमेंट हब के रूप में विकसित करना,

vi. नई स्टार्टअप नीति के तहत नौकरी मांगने के लिए खड़ी युवा आबादी को नौकरी देने वाली युवा आबादी में बदलना

vii. दिल्ली के non-conforming औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना,

viii. दिल्ली में लोकप्रिय फूड हब्ज़ का पुनर्विकास करना,

ix. दिल्ली में क्लाउड किचन क्लस्टर्स की स्थापना करना।

x. दिल्ली में नए इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना करना।

xi. दिल्ली में इ- व्हीकल, सोलर एनर्जी और अर्बन फार्मिंग जैसी योजनाओं के प्रमोशन से ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए ग्रीन जॉब्स लेकर आना

xii. दिल्ली फिल्म पॉलिसी के जरिए टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर से जुड़े रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर स्थापित करना एवं दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन करना।

xiii. दिल्ली में दिल्ली सरकार, विभिन्न विभागों और इनके द्वारा सरकारी एवं निजी उपक्रमों द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यों के आउटकम में एंप्लॉयमेंट ऑडिट की परंपरा शुरू करना।

xiv. दिल्ली में रोजगार ढूंढने वालों और रोजगार देने वालों को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए रोजगार बाजार पोर्टल को अत्याधुनिक और प्रोफेशनल तरीके से रोजगार बाजार 2.0 के रूप में पेश करना।

xv. प्राइवेट स्कूलों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम

xvi. उद्यमिता विकास कार्यक्रम -प्रचार गतिविधियां

37. अब मैं कुछ समय इन स्कीमों का विवरण देने के लिए चाहूंगा।

38. अध्यक्ष महोदय हम जानते हैं कि दिल्ली अनेक 'प्रतिष्ठित बाजारों' का शहर है, जो हमेशा इस शहर का गौरव रहे हैं। प्रत्येक बाजार का अपना महत्व, इतिहास और पहचान रही है। 'हर मार्किट की अपनी कहानी, अपनी पहचान है'। वर्तमान में समूची दिल्ली के खुदरा बाजारों में साढ़े तीन लाख से अधिक दुकानें हैं, जो करीब

साढ़े सात लाख लोगों को रोजगार देते हैं। 'आधुनिक शॉपिंग मॉल्स' के इस युग में भी दिल्ली के प्रतिष्ठित बाजारों के प्रति लोगों का भरोसा अभी भी कायम है. दिल्ली और उसके आसपास के 150- 200 किलोमीटर के दायरे के लोग अभी भी दिल्ली के परंपरागत प्रतिष्ठित बाजारों से शॉपिंग करने में अधिक विश्वास रखते हैं. यहां के व्यापारियों ने आज भी लोगों के दिल में 'दिल्ली का माल मतलब भरोसे का माल' वाली जगह कायम रखी है. यहां ग्राहकों के साथ लूट-खसोट, नहीं होती, धोखाधड़ी नहीं होती, एक अपनेपन का संबंध होता है. दिल्ली का पारंपरिक लोकाचार और खरीदारी की सांस्कृतिक धरोहर अनुभव में आती है. आज दिल्ली के इन परंपरागत प्रतिष्ठित बाजारों के इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं में पुनर्विकास की आवश्यकता है। इन बाजारों की क्षमता है कि अगर सरकार के सहयोग से यहां के व्यापार में थोड़ी भी वृद्धि होती है तो यहां लाखों नई नौकरियां पैदा हो सकती है. दिल्ली सरकार स्थानीय मार्केट एसोसिएशन और अन्य दुकानदारों के साथ मिलकर इन बाजारों को आकर्षक और भरोसे का शॉपिंग एक्सपीरियंस देने वाले बाजारों के रूप में विकसित करेगी। अगले पांच वर्षों में हमारी योजना दिल्ली के इन प्रतिष्ठित बाजारों का पुनर्विकास और कायाकल्प करके इन्हें आकर्षक पर्यटन स्थल जैसा बनाने की है। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण के हिस्से के रूप में, इस वर्ष हम पांच बाजारों से शुरूआत करेंगे और उन्हें भावी विकास के लिए मॉडल के तौर पर प्रयोग करेगें। इसके लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मात्र 5 बाजारों के अंदर से ही अगले पांच साल में कम से कम डेढ़ लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे.

39. अध्यक्ष महोदय दिल्ली में शॉपिंग करना अपने आप में एक सुखद और जीवंत अनुभव है. सरकार की योजना है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश से और विदेशों

से भी लोग दिल्ली में शॉपिंग के लिए आए. जितनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में शॉपिंग के लिए आएंगे उतनी ही तेजी से दिल्ली की इकॉनमी आगे बढ़ेगी और नए-नए जॉब क्रिएट होंगे. दिल्ली में शॉपिंग के लिए देश और दुनिया के लोगों को आमंत्रित करने और इसको एक उत्सव के रूप में अनुभव कराने के लिए हर साल 'दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल' का आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन मूलतः ऐसे उपभोक्ताओं के लिए होगा जो दिल्ली के चुनिंदा बाजारों में अपने परिवार के साथ शॉपिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं.

40. दिल्ली के विभिन्न प्रतिष्ठित बाजारों के साथ मिलकर यह 4 से 6 सप्ताह का शॉपिंग फेस्टिवल होगा। फेस्टिवल के दौरान खरीदारों को विशेष तरह के आकर्षक डिस्काउंट दिए जायेंगे। इस फेस्टीवल के तीन मुख्य आकर्षण होंगे- शॉपिंग, मनोरंजन और खान-पान। हम इस कार्यक्रम को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रकार की मदद देंगे। हमारी सरकार विक्रेताओं (दुकानदारों, रेस्तरां मालिकों, उद्यमियों) को SGST रिफंड देकर उन्हें डिस्काउंट ऑफर करने को प्रेरित करेगी।

41. इससे पर्यटकों (घरेलू और विदेशी) की संख्या में करीब चार लाख की वृद्धि होगी, जिससे होटलों, रेस्तरांओं, पर्यटन व अन्य व्यवसायों को व्यापक लाभ होगा और कुल मिलाकर इन क्षेत्रों में नियोजित 12 लाख लोगों के जीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद है कि इससे व्यापार में कम से कम 25 प्रतिशत का इजाफा होगा।

42. दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज पर ही दिल्ली के बाजारों के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक और फेस्टिवल इस बजट में प्रस्तावित है - दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल. दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल में जहां आम उपभोक्ताओं के नजरिए से

सारी योजनाएं बनाई जाएंगी वहीं दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल में दिल्ली के प्रमुख होलसेल बाजारों के साथ मिलकर दिल्ली, एनसीआर और पूरे देश के उन लोगों के लिए एक नया शॉपिंग एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाएगा जो दिल्ली में होलसेल शॉपिंग के लिए आते हैं। हम सब जानते हैं कि दिल्ली उत्तर भारत में होलसेल ट्रेडिंग का एक बड़ा सेंटर रहा है. आज की दिल्ली में हो रहे व्यापार का 60 परसेंट होलसेल में ही होता है. यह दिल्ली के होलसेल व्यापारियों द्वारा स्थापित भरोसा ही है जिसे आप सरकार आधिकारिक रूप से आगे बढ़ाएगी और दिल्ली के होलसेल मार्केट को एक नई पहचान देगी. दिल्ली सरकार इस फेस्टिवल के लिए दिल्ली के होलसेल व्यापारियों के साथ मिलकर इसका आयोजन तो करेगी ही साथ ही होलसेल ग्राहकों के लिए छूट की आकर्षक योजनाएं भी तैयार कराएगी।

43. अध्यक्ष महोदय आज दुनिया भर में लोग अगर चीन के माल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो उसका एक कारण वहां की सरकार द्वारा होलसेल शॉपिंग को प्रोत्साहन देना भी है. चीन में ज़ेयांग के यूवू शहर में होने वाला होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल, दुनिया भर के ग्राहकों को चीन की तरफ आकर्षित करने में एक गेम चेंजर रहा है, और जब बात दिल्ली के सामान की आएगी तो हमें पूरा यकीन है चीन के सामान के प्रति भरोसे के आगे दिल्ली के सामान के प्रति भरोसा सैकड़ों गुना ज्यादा होगा। और जब दिल्ली का सामान देश के होलसेल बाजार में अपनी जगह बनाएगा तो नौकरियों के कितने अवसर पैदा होंगे इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते।

44. दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल एवं दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल के लिए मैं इस बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं।

45. अध्यक्ष महोदय दिल्ली में दुकानदारों के व्यापार को आगे बढ़ाने और रिटेल मार्केट को बूस्ट देने के लिए सरकार एक और योजना लेकर आ रही है- दिल्ली बाजार। हम सब जानते हैं कि हमारे रिटेल व्यापारियों को ऑनलाइन शॉपिंग से कड़ी प्रति-स्पर्धा का सामना करना पड़ा है, इसे देखते हुए हम अपने स्थानीय व्यापारियों के लिए दिल्ली बाजार नाम से एक ऑनलाइन मंच प्रदान करेंगे ताकि वे वहां आए और ऑनलाइन बिक्री करें। 'गो लोकल' को प्रोत्साहित करते हुए हम एक ऐसा दिल्ली बाजार स्थापित करेंगे, जो 24 घंटे और सातों दिन वर्चुअल स्टोर के रूप में काम करें। यह व्यवस्था हमारे स्थानीय व्यापारियों के लिए 'जीरो सेटअप कोस्ट' यानी 'शून्य खर्च' पर की जायेगी। दिल्ली बाजार का एक बड़ा आकर्षण यह भी होगा कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठे ग्राहक, दिल्ली के प्रसिद्ध आइकोनिक बाजारों का जैसे चांदनी चौक, सरोजनी नगर, करोल बाग आदि का वर्चुअल टूर भी कर सकेंगे और वहां की सड़कों और दुकानों को देखते हुए अपनी खरीदारी भी कर सकेंगे। इसके जरिये हमारे स्थानीय व्यापारियों को अपने हर तरह के ग्राहकों तक पहुंच कायम करने में मदद मिलेगी। मैं इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित करता हूं, जिससे दिल्ली में 10 लाख रिटेल विक्रेताओं को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। अध्यक्ष जी, अपने प्रयासों से अकेले खुदरा क्षेत्र में हमें अगले पांच वर्षों में रोजगार के तीन लाख और अगले एक वर्ष में एक लाख बीस हजार से अधिक रोजगार के नये अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

46. अध्यक्ष महोदय, हमारे दिल्ली के बाजार सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी नहीं है बल्कि हमारे मान सम्मान की भी वजह बनते रहे हैं। दिल्ली का एक ऐसा ही बाजार है गांधीनगर का रेडीमेड गारमेंट और टैक्सटाइल बाजार, जिसके

बारे में हर दिल्लीवासी हमेशा गर्व के साथ बताता है कि 'एशिया का सबसे बड़ा रेडिमेड गारमेंट बाजार हमारे गांधीनगर में हैं'. इस बाजार का डेली टर्नओवर 100 करोड़ रूपये से भी अधिक है और इससे रोजगार के 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 से 3 लाख परोक्ष अवसर पैदा होते हैं। दिल्ली सरकार की योजना है कि रेडिमेड गारमेंट्स टैक्सटाइल के क्षेत्र में दिल्ली की आन बान शान गांधीनगर के इस मार्केट को 'ग्रैंड गारमेंट हब' के रूप में विकसित किया जाए।यहां से तैयार गारमेंट्स कुछ लोग इस्तेमाल में लाए तो बड़ी शान से बता सकें- दिस इज रेडी मेड इन डेल्ही। इसके लिए कानूनी मान्यता, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडेवेलप्मेंट, नए सेवा केन्द्रों का निर्माण और गांधी नगर की री-ब्रैंडिंग, मार्केटिंग और री-पोजिशनिंग की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम से अगले पांच वर्षों में रोजगार के 40 हजार से अधिक नये अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

47. अध्यक्ष महोदय मैंने अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक तथ्य सदन के समक्ष रखा था कि हमें 2030 तक पूरे देश में करीब 9 करोड़ नई नौकरियों का निर्माण करना होगा। इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आने वाले वर्षों में इतनी नौकरियां आएगी कहां से. ये 9 करोड़ नौकरियां पैदा कौन करेगा? पूरे देश के बारे में मैं नहीं कह सकता लेकिन दिल्ली में हमने इसकी अनोखी शुरुआत की है कि हम स्कूल स्तर से ही बच्चों को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी पैदा करने वाला बना रहे हैं. हमने पिछले साल दिल्ली के स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद था 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को अपने बिजनेस आईडियाज पर सफलतापूर्वक काम करके दिखाने की चुनौती देना। तीन लाख से अधिक बच्चों ने 51,000 बिजनेस आइडियाज पर काम किया और आज उनमें से कई हजार बिजनेस आइडियाज ऐसे हैं जिन पर

हमारे यह बच्चे लगातार काम कर रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं और दूसरों को रोज़गार भी दे रहे हैं. अगले वित्त वर्ष से बिजनेस ब्लास्टर के प्रोग्राम को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के साथ साथ दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के साथ भी लागू किया जाएगा। ताकि सरकारी और प्राइवेट दोनों में ही पढ़ने वाले बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने वाली मानसिकता के साथ पढ़ाई करें। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वर्षों में दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के यह बच्चे अपनी युवावस्था के शुरुआती वर्षों से ही देश की 9 करोड़ नई नौकरियों की जरूरत को पूरा करने में अहम योगदान दे रहे होंगे।

48. अध्यक्ष महोदय, जब हम यह कहते हैं कि हमारे बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने तो मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम उन्हें उस तरह का स्वरोजगारी बनाने की बात नहीं कर रहे जिस तरह के स्व- रोजगारी हमारे मुल्क में पिछले कुछ दशकों में खड़े किए गए हैं. मशहूर आर्थिक पत्रकार अंशुमन तिवारी और अनिंद्य सेन गुप्ता ने अपनी हाल की लिखी किताब 'उल्टी गिनती' में लिखा है " स्वरोज़गारी भारत का सबसे अंधेरा कोना है". दिल्ली सरकार स्वरोजगार की अवधारणा इस कड़वी हकीकत से वाकिफ है.

49. मैं सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि भारत के कामगारों में हर दूसरा आदमी सेल्फ एंप्लॉयड है. इसका मतलब है कि भारत में जितने भी लोग कुछ भी काम करते हैं, जिनके पास भी कोई रोज़गार हैं, उनमें से आधे लोग कोई नौकरी करते हैं और आधे लोग सेल्फ एंप्लॉयड हैं. और यह जो हमारी सेल्फ एंप्लॉयड है न, इसमें से 60 फ़ीसदी तो खेती के काम में लगी हैं. और 40 फ़ीसदी लोग अपना कोई काम धंधा करते हैं, जैसे- दुकान चला रहे हैं, वर्कशॉप चला रहे हैं, कोई सेवा दे रहे हैं, रेहड़ी लगाने, रिपेयरिंग, दुकानदारी, कारपेंटर हैं, लोहार हैं,

इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर या सैलून जैसा काम करते हैं." और देश के इन तमाम स्वरोजगारियों में केवल 4 फ़ीसदी स्वरोजगारी ही ऐसे हैं जो अन्य लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं. बाकी के 96 फ़ीसदी स्वरोजगारी अपने काम में खुद के कामगार हैं या फिर उनके परिवार के लोग बगैर किसी पगार के उनके साथ काम कर रहे हैं.

50. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह कोई गलत बात है. स्वरोजगार करके अपना घर चलाना अच्छी बात है. परंतु यह वह पूरा समाधान नहीं है जो हमें राष्ट्रीय स्तर पर चाहिए। हमें राष्ट्रीय स्तर पर नौ करोड़ नए जॉब्स क्रिएट करने हैं तो खाली ऐसे स्वरोज़गारी खड़ा करने से काम नहीं चलेगा जो अपना कुछ काम करके महीने में 10,000 से 15,000 रूपये कमाते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं. नौ करोड़ नई नौकरियां देने के लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पर उद्यमशील स्वरोजगारी खड़े करने होंगे। यानी कि एंटरप्रन्योर्स खड़े करने होंगे। इसी जरूरत को समझते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों में एंटरप्रन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम और बिज़नेस ब्लास्टर प्रोग्राम शुरू कर इसका समाधान निकाला है. इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य ही रखा गया है कि हमारे बच्चे अब नौकरी मांगने वाले नहीं स्कूल कॉलेज से निकले तो नौकरी देने वाले बनकर निकले। इस पाठ्यक्रम से हम दिल्ली के स्कूलों में भविष्य के बिजनेस लीडर तैयार कर रहे हैं।

51. एंटरप्रन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने 'स्टार्टअप' पॉलिसी बनाई है. और मुझे सदन के समक्ष यह जानकारी साझा करते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारी दिल्ली भारत की स्टार्टअप राजधानी है. यहाँ देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं। दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए हमने दिल्ली की स्टार्टअप पॉलिसी को और प्रोग्रेसिव बनाया है. हमारे देश

में अगर कोई युवा स्टार्टअप सेट अप करना चाहता है तो उसे अपना मूल काम छोड़कर सरकार के साथ उलझने में, टैक्स, एनफोर्समेंट, जीएसटी, एमसीडी, पेटेंट जैसे कामों के लिए ही अपना नब्बे परसेंट समय देना पड़ता है. अपने आइडिया पर काम करने के लिए उसके पास केवल 10 परसेंट समय ही बचता है। दिल्ली सरकार की नई स्टार्टअप पॉलिसी यह सुनिश्चित करेगी कि स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं का 100 परसेंट समय अपने आइडिया पर काम करने में जाए और अभी जो उनका 90 परसेंट समय जिन फॉर्मेलिटीज में जाता है उनकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार लेगी। साथ ही दिल्ली सरकार इनक्यूबेशन सेंटर बनाएगी, मार्केटिंग मेंटरिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए सम्मेलन आयोजित करेगी। फाइनेंस के लिए बैंक्स और इन्वेस्टर्स के साथ उनका टाइअप कराएगी। नई स्टार्टअप पॉलिसी के लागू करने के लिए इस साल के बजट में 50 करोड़ रूपये का प्रावधान है.

52. अध्यक्ष महोदय, सरकार ने दिल्ली के लिए एक दिल्ली फिल्म पॉलिसी तैयार की है. यह दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण वातावरण तैयार करेगी| दिल्ली की विविध संस्कृतियां, विविध लोग और विविध परिदृश्य फिल्म निर्माताओं को दिल्ली की ओर आकर्षित करते हैं। दिल्ली सरकार अपनी फिल्म पॉलिसी के माध्यम से इसे और बेहतर बनाकर दिल्ली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्मों के शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांड करेगी। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू पूरी तरह से ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लीयरेंस मैकेनिज्म (ई-फिल्म क्लीयरेंस) होगा, जो 25 से अधिक स्टेकहोल्डर एजेंसियों के साथ सभी अप्रूवल प्रक्रियाओं को तेजी से ट्रैक करेगा| अध्यक्ष महोदय इस पालिसी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दिल्ली में स्थानीय प्रतिभाओं और स्किल्ड युवाओं के

लिए नौकरियों के नए-नए अवसर लेकर आएगी। ये दिल्ली में हाइली स्किल्ड वर्कफ़ोर्स तैयार करेगा जिसे प्रोफेशनल रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार दिल्ली के प्रतिभाशाली युवाओं को छात्रवृत्ति देगी और इंटर्नशिप की व्यवस्था करेगी।

53. दिल्ली सरकार, फिल्म पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए, इस साल से हर साल दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित करेगी। इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से दिल्ली की समृद्ध संस्कृति और विविधता को फिल्मों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा और देशभर की फिल्म बिरादरी को फेस्टिवल में आमंत्रित किया जाएगा। ये फेस्टिवल पर्यटकों को एक सुखद पर्यटन अनुभव देने का काम करेगा।

54. दिल्ली की एक पहचान यहां उपलब्ध व्यंजनों और भोजन की विविधता के लिए भी होती है। दिल्ली के आकर्षक व्यंजनों, परांठे, चाट, छोले-भटूरे, पकोड़े, गोलगप्पे, कबाब और बहुत सारे अन्य खान-पान, जो घरेलू और विदेशी, दोनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। दिल्ली में भोजन और पेय पदार्थ क्षेत्र के व्यापारियों और कर्मचारियों को बढ़ावा देने के लिए हम चार नई नीतियां शुरू कर रहे हैं, जिनसे अगले पांच वर्षों में रोजगार के 60 हजार से अधिक अवसर पैदा होंगे। दिल्ली के प्रमुख फूड हब्स केन्द्रों की पहचान की जायेगी, उनका पुनर्विकास किया जायेगा और दिल्ली की सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत के रूप में उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके साथ ही सरकार दिल्ली में एक फूड़ ट्रक पालिसी भी तैयार कर रही है। इस पॉलिसी के तहत फूड ट्रकों को शहर में निर्दिष्ट स्थानों पर शाम आठ बजे से रात्रि दो बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जायेगी। इससे दिल्ली की नाइट इकोनॉमी भी सुदृढ़ होगी व रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

55. रेस्तरां उद्योग में एक मजबूत हिस्से के रूप में उभरते हुए, दिल्ली में बढ़ती मांग के साथ क्लाउड किचन की संख्या हर साल 20% से अधिक की दर से बढ़ रही हैं। वर्तमान में, दिल्ली में 20,000 से अधिक क्लाउड किचन हैं जो करीब 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 50,000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करते हैं| क्लाउड किचन उन सेक्टर्स में शामिल है, जो नाईट टाइम इकॉनमी को सपोर्ट करते है। राजस्व सृजन की एक बड़ी संभावना के साथ, यह सेक्टर बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की नौकरियों के अवसर पैदा करता है। अध्यक्ष महोदय, वृद्धि की अपार संभावनाओं को देखते हुए बजट 2022-23 में इस इंडस्ट्री की क्षमता को अधिकतम करने के लिए, प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ इन क्लाउड किचन को भूमि प्रदान करने तथा लाइसेंस और नियमों की संख्या को आसान बनाने की योजना बना रहे हैं। ये इंडस्ट्री अगले 5 साल के भीतर 42,000 नए रोजगार पैदा करने की क्षमता भी रखता है|

56. अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देने के लिए तेजी से बढ़ते सेक्टर्स में निवेश करना आवश्यक है| रिटेल तथा फ़ूड एंड बेवरेज सेक्टर इसका उदाहरण है जो 25% की वृद्धि दर से बढ़ रहा है और इनमें उच्च आय वाली नौकरियों को उत्पन्न करने की क्षमता हैं। लेकिन रिटेल सेक्टर में दिल्ली में मॉल्स की भी भारी कमी है| (यहां केवल 10 -12 सफलतापूर्वक चलने वाले मॉल्स और 20 लाख लोगों पर एक माल है।) इससे यहां की नौकरियां और खरीददार एनसीआर की ओर रुख करते है| दिल्ली में प्रति 1000 आबादी पर मॉल स्पेस की उपलब्धता भी सबसे कम है| दिल्ली की तुलना में एनसीआर में ये स्पेस 6 गुणा ज्यादा है|

57. हमारा प्रस्ताव दिल्ली में ग्रेड ए रिटेल और फूड हब विकसित करना है ताकि आज लोग खरीददारी के जिस प्रीमियम अनुभव के लिए एनसीआर जाते है उन्हें दिल्ली में ही विश्वस्तरीय ब्रांड और रिटेल सुविधाएं मिल सके| इसके तहत बस डिपो और टर्मिनलों में उपलब्ध जमीन का उपयोग कर वहां ये हब विकसित किए जाएंगे क्योंकि ये दिल्ली के प्रमुख स्थानों तक आसान पहुंच और उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या वाले क्षेत्र हैं। ये ग्रेड ए स्पेस सभी आधुनिक तकनीकों के साथ तैयार किए जाएंगे जो दिल्ली को भारत में एक शानदार शॉपिंग व फ़ूड हब के रूप में विकसित करेंगे|

58. अध्यक्ष महोदय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आज दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है. और इसकी खास बात यह भी है कि यह एक नॉन पोल्यूटिंग सेक्टर है. परंपरागत रूप से दिल्ली 70-80 के दशक में भारत के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का केंद्र रह चुका है. आज भी दिल्ली इलेक्ट्रोनिक्स और इलेक्ट्रिकल उपकरणों का सबसे बड़ा बाजार है। दिल्ली की खुद की मांग और देश की मांग पूरी करने के उदेश्य से, हम दिल्ली के इलेक्ट्रोनिक सिटी का निर्माण करेंगे। इसके स्थापित हो जाने के बाद 80 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रयोजन के लिए, दिल्ली सरकार बपरौला में 90 एकड़ में प्लग एण्ड प्ले मैन्युफैक्चरिंग केन्द्र की स्थापना करेगी ताकि इलेक्ट्रोनिक कंपनियों को दिल्ली में अपना बेस स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। हम इस कार्यक्रम को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर-ईएमसी कार्यक्रम के सहयोग से करने का प्रयास करेंगे।

59. वर्तमान में दिल्ली में 25 नोटिफाइड नोन-कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जिनमें करीब 16 लाख लोग रोजगाररत हैं। इन क्षेत्रों के पुनर्विकास और अपग्रेडेशन की

आवश्यकता है। अगले पांच वर्षों में दिल्ली सरकार नोन-कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया के पुनर्विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगी। इसके अंतर्गत इन क्षेत्रों को हरित, स्वच्छ और टिकाऊ बनाने और उन्हें व्यापार के अवसरों का विस्तार करने में मदद देने के उपाय किए जाएंगे। बुनियादी ढांचे का पुनर्विकास करने के अंतर्गत हम डेवलपर्स की सेवाएं लेंगे ताकि लेआउट तैयारी और अनुमोदन के साथ, सीवेज, सीईटीपी, पेयजल आपूर्ति, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, रोड़ रीड्वलपमेंट जैसी बुनियादी सेवाएं बेहतर तरीके से जुटायी जा सकें। सरकार कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) भी बनाएगी जिनमें इन औद्योगिक क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार, आर एंड डी, एक्सपीरियंस सेंटर, टूल रूम, प्रोसेसिंग सेंटर, मान्यता प्राप्त टेस्ट लैब, ट्रेनिंग सेंटर, बिजनेस कन्वेंशन सेंटर, रॉ मैटिरीयल बैंक और लॉजिस्टिक्स सेंटर के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र शामिल होंगे। इन क्षेत्रों का पुनर्विकास होने के बाद दिल्ली के लोगों के लिए रोजगार के 6 लाख से अधिक नए अवसर पैदा होंगे।

60. अध्यक्ष महोदय, आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और पानी उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार के 2047 के विजन का एक अभिन्न अंग है। इसे ध्यान में रखते हुए, अगले 5 वर्षों में दिल्ली सरकार कई पहल शुरू करने जा रही है, जो एक लाख से अधिक ग्रीन जॉब्स पैदा करेगी।

61. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली ईवी पॉलिसी-2020 के लॉन्च होने के 18 महीनों के अंदर ही दिल्ली, भारत की ईवी राजधानी के तौर पर उभरी है। 2019-20 में दिल्ली में नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 1.2 फीसद थी, जो फरवरी-2022 में बढ़कर 10 फीसद हो गई है। मुझे यह कहते

हुए भी गर्व हो रहा है कि दिल्ली, आज ईवी की बिक्री में 10 फीसद का आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो यूके, फ्रांस और सिंगापुर जैसे कई विकसित देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी से भी अधिक है। ईवी की बढ़ती हिस्सेदारी के चलते अगले पांच वर्षों में ईवी की बिक्री, मरम्मत और रखरखाव, ईवी चार्जिंग स्टेशनों के संचालन व उसके रखरखाव में 20 हजार नए रोजगार पैदा होंगे। इसके अलावा, दिल्ली सरकार आगामी वर्ष में 33 फीसद रिजर्वेशन के साथ महिला ड्राइवरों के लिए 4,200 से अधिक ई-ऑटो शुरू कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सहमति से हम अगले पांच वर्षों के लिए हर साल 5,000 ई-ऑटो परमिट जारी करेंगे और इससे 25 हजार नई नौकरियां पैदा होंगी।

62. दिल्ली, रूफटॉप सोलर यूनिटस को अपनाने की दिशा में लगातार प्रगति कर रही है। रूफटॉप 16 प्लांटों की स्थापित क्षमता पहले ही 900 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। दिल्ली सरकार अगले पांच वर्षों में रूफटॉप सोलर प्लांटों की स्थापित क्षमता को 2,500 मेगावाट (पीक) तक पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नई सोलर पॉलिसी भी लाएगी, जो दिल्ली की वार्षिक ऊर्जा की डिमांड में 10 फीसद का योगदान देगी। इससे, इस क्षेत्र में सेल्स, निर्माण श्रमिकों, इलेक्ट्रीशियन, तकनीशियनों और इंजीनियरों के लिए 40 हजार नौकरियां पैदा होंगी।

63. दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाने, पौष्टिक जैविक भोजन की आपूर्ति बढ़ाने और महिलाओं को घर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार आईएआरआई (पूसा संस्थान) के सहयोग से 'स्मार्ट अर्बन फार्मिंग' की शुरूआत करेगी। यह भारत में किसी भी राज्य के लिए अपनी तरह की सबसे बड़ी पहल

होगी, जहां दिल्ली सरकार पूरे दिल्ली के मोहल्लों में कार्यशालाएं आयोजित करेगी और 'स्मार्ट अर्बन फार्मिंग' को जन आंदोलन बनाने के लिए सब्सिडी युक्त सामग्री और प्रशिक्षित माली के जरिए दिल्ली की महिलाओं को विशेष तौर पर सहायता प्रदान करेगी। इससे अगले पांच वर्षों में दिल्ली में 25 हजार नई नौकरियों का सृजन होगा।

64. दिल्ली सरकार ने 750 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ दिल्ली की 600 से अधिक झीलों और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत की है, जो दशकों से उपेक्षित दिल्ली के जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करेगा, जिसने इन्हें डंपयार्ड में बदल दिया था। यह, बड़े पैमाने पर इन जलाशयों के चल रहे मरम्मत कार्य और रखरखाव के लिए 6 हजार से अधिक ग्रीन जॉब्स पैदा करेगा, ताकि एक बार पुनर्निर्मित होने के बाद, ये जलाशय खराब न हों।

65. अध्यक्ष महोदय, कोरोना की पहली लहर के बाद जब पूरे देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हुए उस दौरान जुलाई 2020 में दिल्ली सरकार ने नौकरी देने वाले व नौकरी चाहने वालों को जोड़ने के लिए रोज़गार बाज़ार की शुरुआत की। रोजगार बाज़ार 1.0 की सफलता दर्शाती है कि इसमें 15 लाख से अधिक नौकरी चाहने वालों ने रजिस्ट्रेशन किया और 10 लाख नौकरी के अवसर प्राप्त हुए। इतने कम समय में इतनी ज्यादा नौकरियां दिलवाने वाला शायद यह देश के किसी भी राज्य का सबसे ज्यादा सफल प्रयोग होगा। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने अगले साल में रोज़गार बाज़ार 2.0 लॉन्च करने का निर्णय

लिया है जो एक आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन होगा।

66. रोजगार बाज़ार 2.0 स्मार्ट मैचिंग, प्लेसमेंट ट्रैकिंग, एम्पलोयर्स के वेरिफिकेशन और एक मजबूत एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म सहित कई नई सुविधाओं से लैस होगा। इस पोर्टल के माध्यम से हमारा लक्ष्य दिल्ली के युवाओं को, और खास कर के महिलाओं को, हर साल कम से कम 1 लाख नौकरियां मुहैया करना है। इसके साथ-साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नौकरी चाहने वालों को टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज एक्सप्लोर करने, करियर काउंसलर के साथ वन-टू-वन सेशन, सरकारी नौकरियों व सरकार द्वारा रोजगार संबंधी दिए जाने वाले सोशल बेनिफिट्स की जानकारी सहित कई अन्य वैल्यू-एडेड सेवाएं भी मिलेंगी।

67. अध्यक्ष महोदय, इस 'रोज़गार बजट' का एक अहम उद्देश्य महिलाओं का रोज़गार और आर्थिक विकास है। वर्किंग फ़ोर्स में महिलाओं की भागीदारी में भारत Asia में सबसे पिछड़े देशों में से है। जबकि भारत में पिछले तीन दशक में बेहतर आर्थिक प्रगति के बावजूद यह हैरान करने वाली बात है कि इस दौरान महिलाओं की वर्किंग फोर्समें भागीदारी में गिरावट आई है। 1999 में 34% से 2019 में ये घटकर 20% हो गई, जो दुनिया भर में देखे जा रहे ट्रेंड के विपरीत है। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश में वर्किंग फ़ोर्स में महिलाओं की भागीदारी 30% और चीन में 60% है। इसके अतिरिक्त, महामारी के दौरान उत्पन्न बेरोजगारी से महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। सारे अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत है की जब तक भारत की महिलाएं देश की वर्किंग फोर्स से बाहर रहेगी, तब

तक भारत का विकासशील से एक विकसित देश बनने का सिर्फ एक सपना ही रहेगा। इसी मद्देनज़र, इस साल के बजट में पेश की गई नई योजनाओं में महिलाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है|

68. गांधीनगर में ज्यादातर रिटेल, डिजाइन और रेडीमेंड कपड़ों का काम महिलाओं द्वारा किया जाता है। गांधीनगर को जैसे ही गारमेंट डिजाइन और असेंबली के हब के रूप में विकास करेंगे, महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दुनिया भर में, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली इकाइयां ज्यादातर महिलाओं को रोजगार देती हैं। दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक शहर की स्थापना से फिर से महिलाओं के लिए रोजगार के अपार अवसर पैदा होंगे| दिल्ली में अर्बन फार्मिंग, इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक बस की चलन में ख़ास कर महिलों को नए रोज़गर के अवसर देने पर बल दिया जायेगा। रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल में भी महिलाओं को नए रोजगार कैसे मिले और उनकी दिल्ली के अर्थव्यवस्था में भागीदारी कैसे बढे इस पर ख़ास ध्यान दिया जायेगा।

69. इस तरह विभिन्न क्षेत्रों में अगले 5 साल में कम से कम 20 लाख रोजगार पैदा होंगे। इसके साथ ही सरकार एक और महत्वपूर्ण योजना लेकर आ रही है. सरकार के हरेक विभाग में, दिल्ली सरकार के किसी भी संस्थान में, इस सदन द्वारा पास किए जा रहे बजट का एक एक रुपए के खर्च करने से, वह पैसा चाहे शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च हो रहा हो, उससे सड़कें बनाई जा रही हो, बिल्डिंग बनाई जा रही हो, पुल बनाए जा रहे हो, स्कूल अस्पताल कॉलेज चलाए जा रहे हो, बिजली पानी की व्यवस्था में यह पैसा खर्च किया जा रहा हो, कॉल सेंटर, कला संस्कृति आदि के क्षेत्र की सेवाएं ली जा रही हो.... एक एक रुपये के

खर्च किए जाने के फलस्वरूप कितने लोगों को रोजगार मिला इसका पूरा हिसाब किताब रखा जाएगा।इसके लिए सरकार बाकायदा हर एक विभाग का एंप्लॉयमेंट ऑडिट का प्लान लेकर आ रही है. यह अपने आप में देश में पहला कदम होगा जहां जनता के टैक्स के पैसे से हो रहे कामों के सामान्य आउटकम के साथ-साथ एंप्लॉयमेंट आउटकम का भी ऑडिट होगा।

70. जैसा कि मैंने कहा कि यह सभी कार्यक्रम अगले 5 वर्ष के लिए प्रस्तावित हैं. और इन के सफल क्रियान्वयन से जो नई नौकरियां निकलेगी उसमें भी अगले 5 साल में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां निकलने की उम्मीद है. इन कार्यक्रमों के लिए अगले 5 साल के दौरान करीब 4,500 करोड रुपए की आवश्यकता होगी। पहले वर्ष के लिए इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 800 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूं.

स्वास्थ्य सेवाएं

71. अध्यक्ष महोदय अब मैं स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रमुख प्रस्ताव सदन के समक्ष रखूंगा। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस सदन में प्रस्तुत पिछले सात बजट में हर बार शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता रहे हैं. दिल्ली में रह रहे हर नागरिक के लिए वह चाहे अमीर हो या गरीब हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, स्त्री हो या पुरुष हो, हर व्यक्ति के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल का अहम हिस्सा है. नए अस्पताल बनाने से लेकर मोहल्ला क्लीनिक जैसी नई अवधारणा पर सफलतापूर्वक काम करना केजरीवाल सरकार की पिछले 7 वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से रही है. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार दिल्ली के

नागरिकों को 520 आम आदमी मौहल्ला क्लिनिक, 29 पॉलीक्लिनिक और 38 मल्टी स्पेशिलिटी/सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा रही है। 94 पॉलीक्लिनिक, मौजूदा औषधालयों का उन्नयन कर स्थापित किए जा रहे हैं। मौहल्ला क्लिनिकों की संख्या भी बढ़ाकर 1,000 की जाएगी। मैं, 2022-23 के बजट में आम आदमी मौहल्ला क्लिनिक और पॉलीक्लिनिक के लिए 475 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

72. दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा स्थापित मोहल्ला क्लीनिक के मॉडल की सफलता को देखते हुए अब देश के कई राज्यों में छोटे कस्बों और गांवों तक मोहल्ला क्लीनिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. 2015 में मोहल्ला क्लीनिक क्यों बनाए गए? और मोहल्ला क्लीनिक में किस समस्या का समाधान किया है, आज रोजगार बजट में इसके लिए प्रस्ताव रखते वक्त मैं मोहल्ला क्लीनिक के पीछे की अवधारणा को भी स्पष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय हमें समझना होगा कि "भारत की नई गरीबी बीमारी से निकल रही है"। भारत में हर साल 5.50 करोड़ लोग यानी की पूरी आबादी का 4.6% लोग बीमारी की वजह से गरीब हो जाते हैं. इनमें से 72 फ़ीसदी केवल प्राथमिक चिकित्सा पर हो रहे खर्च के कारण गरीब होते हैं. यहीं पर मोहल्ला क्लीनिक की आवश्यकता है। इसीलिए दिल्ली में यह सफल हुआ. और आज अगर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रही है, महामारी और महामंदी के इस दौर में अगर दिल्ली की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो इसमें मोहल्ला क्लीनिक ने एक अहम भूमिका निभाई है. मुझे सदन को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब तक 5 करोड़ 49 लाख मरीज इन मोहल्ला क्लीनिक में प्राथमिक उपचार लेकर जा चुके हैं. यही वह लोग हैं

अगर इन्हें समय पर और सही से प्राथमिक उपचार ना मिलता, मोहल्ला क्लीनिक में एक अच्छे डॉक्टर द्वारा पूरी तरह निशुल्क उपचार ना मिलता तो संभवतः इनमें से बहुत से लोग बीमारी की वजह से गरीबी की तरफ चल पड़ते।

73. दिल्ली सरकार ने आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक को विस्तार देते हुए दिल्ली के स्कूलों में भी आम आदमी स्कूल क्लीनिक शुरू किये गए हैं। फिलहाल 20 स्कूलों में यह क्लीनिक खोल दिए गए हैं और यहां हर एक बच्चे का, हर 6 महीने में सारे चेकअप योग्य डॉक्टर और नर्स के द्वारा किया जाना शुरु हो गया है. साथ ही हर एक 'आम आदमी स्कूल क्लीनिक' में एक- एक मनोचिकित्सक भी लगाए जा रहे हैं ताकि बच्चों के मानसिक विकास, उनकी मानसिक उलझन, या अगर वह किसी मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं तो इसकी जांच भी हर 6 महीने में, हर एक बच्चे की होती रहे.

74. हमारी सरकार ने मौजूदा अस्पतालों के विस्तार और अपग्रेडशन तथा नए अस्पताओं का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इनके तहत बुराड़ी में 768 बिस्तरों का अस्पताल पूरा हो चुका है और कोविड रोगियों के लिए 450 बिस्तरों के साथ काम कर रहा है। इसी प्रकार अम्बेडकर नगर अस्पताल भी कोविड रोगियों के लिए 200 बिस्तरों की क्षमता के साथ 25 जुलाई 2020 से काम शुरू कर चुका है। इंदिरा गांधी अस्पताल द्वारका में भी कोविड रोगियों के उपचार की व्यवस्था की गई है। अगले साल यह अस्पताल 1,241 बिस्तरों की अपनी पूरी क्षमता से काम शुरू कर देगा।

75. पंद्रह मौजूदा अस्पतालों की रि-मॉडलिंग का काम शुरू हो गया है और इसके अलावा चार नए अस्पतालों के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। नए अस्पतालों

के बन जाने और मौजूदा के रि-मॉडलिंग का काम पूरा हो जाने के बाद इनमें 16,000 बिस्तरों की क्षमता का इजाफा होगा। मैं, नए अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा सरकारी अस्पतालों के रि-मॉडलिंग के लिए 1,900 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं।

76. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली आरोग्य कोष के तहत निशुल्क उपचार, सर्जरी, रेडियोलॉजी, क्लिनिकल सेवाएं उन रोगियों को निजी अस्पतालों के जरिये उपलब्ध कराई जा रही है जिनका कई कारणों के चलते दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलना संभव नहीं हो पाता। इस योजना के लिए अगले वर्ष में 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।

77. यह सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को आगे बढ़ाने से संबंधित काम है. लेकिन इसके अलावा दो बड़े कदम जो सरकार उठाने जा रही है और जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और इस साल से उन पर काम होना शुरू हो जाएगा, वह हैं –

(i) पहला है, (a) हॉस्पिटल इनफॉरमेशन मैनेजमेंट सिस्टम और (b) हेल्थ कार्ड: इसके तहत सभी नागरिकों को, उनके मतदाता पहचान पत्र और जनसंख्या रजिस्टर के आधार पर, क्यूआर कोड आधारित, ई-हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इससे रोगियों की पहचान करने और जिओ टैगिंग के साथ उनकी बीमारी की बुनियादी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह प्रणाली फैमिली ट्री यानि परिवार के सदस्यों की जानकारी प्राप्त करने में भी मदद करेगी। इससे दिल्ली के सभी नागरिकों को बेहतर समय पर इलाज उपलब्ध करवाने में काफी आसानी

हो जायेगी । इन योजनाओं के लिए के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में 160 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है।

(ii) दूसरा है, हेल्थ हेल्पलाइन: हेल्थ कार्ड धारकों के लिए यह एक निशुल्क 24 घंटे की हेल्पलाइन होगी जिस पर फोन करके कोई भी हेल्थ कार्ड धारक किस बीमारी के लिए कहां इलाज कराना है, क्या करना चाहिए जैसी सलाह ले सकता है. इस हेल्पलाइन पर हेल्थ कार्ड धारकों को अस्पतालों में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिलाने की सुविधा होगी।

78. मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में आम जनमानस को स्वस्थ रखने के लिए योग और ध्यान को आम जनमानस तक निशुल्क ले जाने के लिए आम आदमी योगशाला शुरू की गई है. इसकी घोषणा मैंने पिछले बजट में की थी. और मुझे खुशी है कि कोरोना की लहरों के बीच भी दिल्ली सरकार के औषध विज्ञान अनुसंधान विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षित 450 योग शिक्षक रोजाना से अधिक 15000 लोगों को उनकी सुविधा और समय अनुसार योग सिखा रहे हैं। लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपने आप में एक यह बहुत बड़ा अभियान है जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी योग को जन आंदोलन बनाना है के संकल्प के साथ आगे बढ़ा रहे हैं. यह योजना अगले साल भी चलती रहेगी. इसके लिए बजट में अलग से 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

79. अध्यक्ष महोदय जब मैं इस सदन के समक्ष केजरीवाल सरकार का मॉडल रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं तो थोड़ी सी बात मैं स्वास्थ्य और रोजगार के रिश्ते पर भी करना चाहता हूं.

80. अध्यक्ष महोदय अगर कोविड महामारी ना आई होती तो शायद लोगों का ध्यान इस ओर न जा पाता, कि किसी देश की आर्थिक प्रगति का उस देश के लोगों के स्वास्थ्य से सीधा रिश्ता होता है। नीति विश्लेषक और आर्थिक इतिहास के विशेषज्ञ अनिंद्य सेन गुप्ता लिखते हैं कि - "स्वास्थ्य की व्यवस्था आर्थिक चर्चाओं का हिस्सा नहीं होती। लेकिन महामारी के बाद दुनिया समृद्धि के जो नए पैमाने को लागू करेगी उसमें यह तय होगा कि जिस मुल्क का स्वास्थ्य ढांचा जितना चुस्त होगा उस पर इतने बड़े दांव लगाए जाएंगे"... ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हमारी आबादी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी उत्पादकता घटती है. ऐसे में वर्किंग पॉपुलेशन से और बेहतर प्रोडक्टिविटी की जरूरत है. और ऐसा करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना ही एकमात्र रास्ता है जिससे 55 साल की आयु वाले व्यक्ति से 45 साल की आयु वाले व्यक्ति के बराबर उत्पादन कराया जा सके. आज देश में स्वास्थ्य तकनीकों की कमी नहीं है. नए प्रयोग और अविष्कार लगातार हो रहे हैं. लोगों को बीमारियों से बचा कर और खास तौर पर उन्हें प्राथमिक उपचार सही से और समय पर उपलब्ध कराकर बड़ी आबादी की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति $100 के खर्च से जीवन में प्रतिवर्ष एक स्वास्थ्य वर्ष बढ़ाया जा सकता है.

81. अलग-अलग बीमारियों पर नियंत्रण, तुरंत उपचार और सभी को स्वास्थ्य जैसी कोशिश किसी भी देश के लिए ग्रोथ की गारंटी है। मैकेंजी की गणना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर कर 2040 तक दुनिया के जीडीपी में 12 ट्रिलियन डॉलर जोड़े जा सकते हैं जो ग्लोबल जीडीपी का 8 फ़ीसदी होगा यानी कि हर साल 0.4% की सालाना बढ़ोतरी।

82. भारत में सरकारों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने पर, प्रत्येक 100 रुपये के निवेश पर अर्थव्यवस्था में 400 रुपये का आर्थिक रिटर्न संभव है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने से जीवन में प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष, करीब 24 स्वस्थ दिन बढ़ाए जा सकते हैं और 2040 तक जीडीपी में करीब 45 हज़ार अरब रुपये जोड़े जा सकते हैं, जो भारत के कोविड के पहले की जीडीपी का करीब 6 फ़ीसदी होगा।

83. इसीलिए पिछले 7 साल से दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सुविधाओ पर लगातार अपने खर्चे को बढ़ाती आ रही है. बात सिर्फ लोगों को स्वस्थ रखने की नहीं है बात लोगों को स्वस्थ रखते हुए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और नए नए रोजगार के अवसर पैदा करने की भी है.

84. मैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,769 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित करता हूं। इसमें 7,522 करोड़ रुपए का राजस्व बजट और 2,247 करोड़ रुपए का पूंजीगत बजट शामिल है। 5,567 करोड़ रुपए की राशि स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं, क्रार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रार्यान्वयन के लिए निर्धारित की गई है।

शिक्षा

85. अध्यक्ष महोदय, केजरीवाल मॉडल ऑफ़ गवर्नेंस के पिछले 7 साल के दौरान दिल्ली को मजबूत बनाने के लिए पांच महत्वपूर्ण पिलर रहे हैं - बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार.

86. आज दुनिया भर में हम जिन देशों को विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहे हैं उनमें अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का इतिहास तीन महत्वपूर्ण कारकों पर आधारित रहा है -

a. अर्थव्यवस्था की पारंपरिक ताकत

b. सरकारों का राजनीतिक साहस और दूरदर्शिता, तथा

c. आबादी की शिक्षा की गुणवत्ता

87. परंपरागत रूप से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था रही है. हमारी ताकत हमेशा हमारे लोग और हमारे प्राकृतिक संसाधन रहे हैं. इसके बावजूद अगर आजादी के 75 साल में भी हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था ही बने हुए हैं और विकसित देश नहीं बन पाए हैं तो उसका बड़ा कारण है कि सरकारों ने राजनीतिक साहस और दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। 2015 में ऐसी गलती को ठीक करते हुए केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत हमारी सरकार ने एक साहसिक और दूरदर्शी कदम उठाया। वह यह था कि बड़ी-बड़ी पारंपरिक प्राथमिकताओं और इच्छाओं को किनारे करते हुए शिक्षा को सबसे बड़ी राजनीतिक प्राथमिकता बनाया। और पिछले 7 साल में इस संकल्प के साथ काम करते हुए लगातार शिक्षा के बजट में अधिकतम आवंटन किया। इस आवंटन के दम पर शानदार सरकारी स्कूल भवनों का निर्माण हुआ. सरकारी स्कूलों में शानदार लैब, लाइब्रेरी, क्लासरूम, बैठने के लिए डेस्क, 21वीं सदी के आधुनिक डिजिटल पढ़ाई की सुविधाएं, शिक्षकों की देश विदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग, विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं विकसित करने जैसे काम संभव हो सके. अगर 2015 में ये कदम नहीं उठाए गए होते तो आज दिल्ली के अधिकतर

सरकारी स्कूल मकड़ी के जाले लगे हुए, टेंट वाले स्कूल के रूप में ही पहचान बनाए रखते।

88. सात साल की इस यात्रा के बाद मैं बेहद आत्मविश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति ने दिल्ली में अर्थव्यवस्था की क्रांति का आधार तैयार कर दिया है.

89. दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने अब तक कोरोना महामारी के बावजूद सीबीएसई परीक्षाओं में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए हैं और लगभग असंभव समझे जाने वाले 100% पासिंग परसेंटेज रिजल्ट (वस्तुतः 99.84%) को हासिल करके दिखाया है। अब अमीर हो या गरीब, सब के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा लेकर नीट और आईआईटी-जेइइ जैसी परीक्षाओं में हर साल नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं. क्वालिटी एजुकेशन के नए मापदंड तय करने के लिए हमने दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड का गठन किया है. और साथ ही दिल्ली में अलग-अलग विषयों की स्पेशलाइज़्ड पढ़ाई के लिए स्कूल ऑफ स्पेशलाइड एक्सीलेंस खोले हैं. इन स्कूलों में पढ़ाई के अंतरराष्ट्रीय तरीके अपनाए जा रहे हैं और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का आकलन भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है. ये स्कूल, प्रमुख विश्वविद्यालयों, विशेषज्ञों और उद्योग जगत के साथ साझेदारी भी करते हैं ताकि इंटर्नशिप, एपरेंटिसशिप, मास्टर क्लास, गेस्ट लेक्चर और फील्ड विजिट के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को और गहरा बनाया जा सके।

90. दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया गया हैप्पीनेस पाठ्यक्रम और देशभक्ति पाठ्यक्रम अब प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों और अभिभावकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. अभिभावकों और अध्यापकों की मांग पर अब

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में भी हैप्पीनेस पाठ्यक्रम और देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है.

91. महोदय, मैं वर्ष 2022-23 के दौरान शिक्षा क्षेत्र में लागू किए जाने के लिए कुछ नए कार्यक्रम प्रस्तावित कर रहा हूं।

92. मैं, चिराग इन्क्लेव नई दिल्ली में एक स्कूल साइंस म्यूजियम स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच विज्ञान के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो किताबों और वीडियोस के माध्यम से उन्हें तिलिस्म की दुनिया लगते हैं, वह इस संग्रहालय में जाकर उन्हें आसानी से समझ सकेंगे। यह स्कूल साइंस म्यूजियम बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और रूचि विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। मैं, 2022-23 के बजट में स्कूल साइंस म्यूजियम के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूं।

93. अध्यक्ष महोदय, बेघर परिवारों के बच्चे जो सड़क किनारे, फुटपाथ, फ्लाईओवर और सीढियों के नीचे या खुले पूजा स्थलों, मंडप, रेलवे प्लेटफॉर्म इत्यादि पर रहते हैं वे आश्रय, भोजन और शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। सरकार ने इन बच्चों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए हैं। हालांकि ये उपाय आंशिक रूप से ही सफल रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि भोजन और आश्रय जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं हो जाती। कम उम्र के इन सुविधा वंचित बेघर बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए दिल्ली सरकार ने आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने का फैसला किया है। ये स्कूल बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ रहने की भी सुविधा देंगे और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने का

प्रयत्न करेंगे। इस नई पहल के लिए मैं बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं।

94. मैंने अपनी पिछले बजट में दिल्ली के सभी क्लास रूम को अगले 5 साल में स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम में बदलने की योजना रखी थी। इसका पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो गया है. इस साल से हम अगले 4 साल में अपने सभी स्कूलों के सभी क्लासरूम्स को डिजिटल क्लासरूम में बदलने का काम शुरू कर रहे हैं.

95. हमने राजेंद्र नगर के सर्वोदय स्कूल में एक आधुनिक मोंटेसरी लैब बनाई है. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की दिशा में मोंटेसरी लैब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. आने वाले समय में हम 100 और स्कूलों में इसी तरह की मोंटेसरी लैब स्थापित करेंगे।

96. स्कूलों में खेल को आगे बढ़ाते हुए हमने 100 चयनित स्कूलों में, स्थानीय बच्चों और समाज की जरूरतों के हिसाब से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू कर दिया है.

97. स्कूल के बाद की शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने हायर, टेक्निकल एजुकेशन संस्थानों का विस्तार पिछले 7 साल में बहुत तेजी से किया है. 2015 में सरकार बनने के बाद केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली में अब तक 5 नई यूनिवर्सिटी खोली जा चुकी है. ये हैं - 2015 में शुरू हुई दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (DPSRU), इसके बाद 2018 में बनी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी(NSUT), 2020 में बनी दिल्ली स्किल एंड

एंटरप्रन्योरशिप यूनिवर्सिटी(DSEU), 2021 में बनी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और 2022 में बनी Delhi Teachers University. इसके अलावा अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दो नए कैंपस कर्मपुरा और लोधी रोड पर खोले गए. साथ ही DTU का ईस्ट दिल्ली केंपस खोला गया. आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली केंपस इस साल से शुरू हो रहा है।

98. अगर दिल्ली के स्कूलों से निकल रहे छात्रों के हायर एजुकेशन के बढ़ रहे अवसरों को देखें तो पिछले 7 साल में केजरीवाल सरकार के दौरान इसमें बेहद शानदार काम हुआ है. डीटीयू में 2014 में 2,226 छात्रों को दाखिला मिला था और 2021 में डीटीयू का इनटेक 4,105 गया है. इसी तरह NSUT में 2014 में कुल 913 बच्चों का दाखिला हुआ था, लेकिन यूनिवर्सिटी बनने के बाद अब 2021 में यहां 3,200 बच्चों का दाखिला हुआ है. आईपी यूनिवर्सिटी में 2014 में दाखिले के लिए 28,000 सीटें थी जो अब बढ़कर 38,000 हो गई है. IGDTUW में 2014 में 300 दाखिले की सीटें थी जो अब बढ़कर 1,350 हो गई हैं. अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 2014 में दाखिले के लिए 1,800 सीटें थी जो अब बढ़कर 4,700 हो गई हैं.

99. दिल्ली skill और entrepreneurship यूनिवर्सिटी के 15 कैंपस इस साल शुरू हो चुके हैं और इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, डिप्लोमा आदि कोर्सेज के लिए 7,145 नई सीटों पर इस साल एडमिशन हुए. इस साल शुरू हुए 15 कैंपस के साथ-साथ अगले साल दिल्ली skill और entrepreneurship यूनिवर्सिटी के 11 और कैंपस में पढ़ाई इस साल से शुरू हो जाएगी और इसमें इसी साल से हर साल, ढाई हजार और बच्चों को दाखिला मिल सकेगा।

100. दिल्ली खेल विश्वविद्यालय ने अपना काम शुरू कर दिया है. जैसा मैंने पहले भी सदन में कहा था कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की संकल्पना एक ऐसे विश्वविद्यालय के रूप में की गई है जहां केवल और केवल देश को अच्छे खिलाड़ी, मेडल लाने वाले खिलाड़ी देने पर काम किया जाएगा। मुझे इस सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि अगले सत्र से दिल्ली खेल विश्वविद्यालय में देश भर से करीब ढाई सौ खेल प्रतिभाओं को दाखिला देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इन खेल प्रतिभाओं को अभी से भावी ओलंपिक चैंपियन के रूप में तैयार किया जाएगा।

101. इसी तरह हाल ही में शुरू की गई दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी ने भी बहुत तेजी से अपना काम करना शुरू कर दिया है और हमारी पूरी कोशिश है कि भारत सरकार से जरूरी मंजूरी हासिल करने के बाद अगले सत्र से यहां भी B.Ed के कोर्स की पढ़ाई शुरू हो सके.

102. महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शिक्षा क्षेत्र में 16,278 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 14,412 करोड़ रुपए राजस्व के तहत और 1,866 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के तहत शामिल हैं।

आवास और शहरी विकास

103. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों और दिल्ली की झुग्गीबस्तियों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हमेशा महत्व दिया है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सीसीटीवी कैमरा और स्ट्रीट लाइट लगाने सहित सड़क, सीवर, पार्क इत्यादि का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया है। हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले यह काम बहुत छोटे पैमाने पर केवल

895 अनधिकृत कॉलोनियों में किया गया था, लेकिन 2015 के बाद से यह सुविधाएं प्रत्येक अनधिकृत कॉलोनी और झुग्गीबस्ती को तेजी से उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 1,797 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1,414 में निर्माण कार्य या तो पूरा हो चुका है या प्रगति पर है। मैं, वर्ष 2022-23 के बजट में इसके लिए 1,300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं।

104. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के सराहनीय प्रयासों से उत्तरी नगर निगम, दक्षिणी नगर निगम और पूर्वी नगर निगम की सभी बस्तियों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। 634 बस्तियों में लगभग 1,051 किलोमीटर की सिमेंटेड कंक्रीट फुटपाथ बनाई गई है और 266 किलोमीटर लंबे नालों का निर्माण किया गया है।

105. महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में आवास और शहरी विकास योजनाओं के लिए 5,766 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूं।

जलापूर्ति और स्वच्छता

106. अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को दो और बड़े सपने दिए हैं जिस पर खुद मुख्यमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं. वो हैं -

a. दिल्ली में 24 घंटे पीने का साफ पानी लोगों के घरों में आए,

b. और हमारी यमुना निर्मल साफ सुंदर पानी वाली नदी बन जाए

107. जैसा कि मैंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री दिन रात इन दोनों सपनों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। जिस तरह 2015-16 में उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए 24 घंटे

बिजली का सपना सच करके दिखाया था वैसे ही अब केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में 24 घंटे पीने का साफ पानी मिलने का सपना भी जल्द ही सच होगा। मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली में पानी की उपलब्धता 10 % बढ़ चुकी है. पहले दिल्ली में रोजाना 915 एमजीडी पानी उपलब्ध होता था यह अब बढ़कर 985 एमजीडी हो गया है. दिल्ली को बाहर से मिल रहे पानी के बेहतर प्रबंधन, और बारिश के पानी की बेहतर हार्वेस्टिंग से आने वाले 3 साल में 24 घंटे पानी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

108. दिल्ली वासियों को 20 किलो लीटर प्रति माह , प्रति उपभोक्ता, पीने का पानी मुफ्त उपलब्ध कराने की जो योजना 2015 में शुरू की गई थी वह इस साल भी लगातार जारी रहेगी। औसतन 6.50 लाख उपभोक्ताओं के पानी के बिल इस योजना के तहत हर महीने जीरो आते हैं।

109. पूरी दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हंड्रेड परसेंट सीवर पहुंचाने का काम इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

110. यमुना को साफ करने की माननीय मुख्यमंत्री की मुहिम अब आगे बढ़ चली है. यमुना में गिरने वाले सभी नालों को इंटरसेप्ट करके या तो एसटीपी में ले जाकर उसके पानी को साफ किया जाएगा या फिर उसका इन-सीटू ट्रीटमेंट करके उसे साफ पानी में बदला जाएगा। यह सभी योजनाएं तेजी से चल रही हैं. और 2 साल में यमुना को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार का यह संकल्प है कि दिल्ली वासियों की तरफ से गंदे पानी की एक बूंद भी यमुना के पानी में ना गिरे.

111. गंदे नालों और सीवर के ट्रीटमेंट किए गए पानी को इस्तेमाल करने की पॉलिसी पर अमल शुरू कर दिया गया है जिसके अंतर्गत यह पानी बड़े ग्रीन बेल्ट, फॉरेस्ट, फॉर्म हाउस और हॉर्टिकल्चर के लिए दिया जाएगा। इससे हजारों बोरवेल भी बंद होंगे और दिल्ली के नीचे का वाटर लेवल भी बढ़ेगा।

112. नजफगढ़ ड्रेन को पुनर्जीवित करने के लिए विस्तृत योजना पर काम शुरू हो गया है. पूरे नजफगढ़ ड्रेन में फ्लोटिंग वेटलैंड और फ्लोटिंग एयरेटर लगाकर यहां पानी को साफ किया जाएगा। नजफगढ़ ड्रेन की इंन सीटू सफाई का काम और दोनों तरफ की सड़कों के सौंदर्यीकरण का काम भी साथ साथ शुरू होगा। नजफगढ़ ड्रेन जो पहले साहिबी नदी के नाम से जाना जाता था, अब सीवर के गंदे पानी के कारण इसमें नजफगढ़ ड्रेन के रूप में पहचाना जाता है , इसे साफ कर और इसके दोनों तरफ की सड़कों का सौंदर्यीकरण कर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और दिल्ली की साहिबी नदी को वापस उसके स्वरूप में लाया जाएगा। इसके लिए अलग से 705 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है.

पर्यावरण और वन

113. अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण का विषय पूरी दिल्ली के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जैव विविधता में कमी, ध्वनि प्रदूषण, दिल्ली के पर्यावरण के समक्ष गंभीर चुनौतियां हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमारी सरकार ने 1 अक्तूबर 2021 से 28 फरवरी 2022 के दौरान "Ten Point – Winter Air Action Plan" कार्यान्वित किया। इसके तहत पराली जलाने पर नियंत्रण, एंटी डस्ट कैंपेन , कूड़ा-करकट जलाने की रोकथाम, आतिशबाजी

पर पाबंदी, स्मॉग टावर की स्थापना, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले स्थलों की पहचान, ग्रीन वॉर रूम को मजबूत करना, ई-कचरा पार्क की व्यवस्था और वाहन प्रदूषण नियंत्रण के उपाय शामिल हैं।

114. दिल्ली सरकार न केवल दिल्ली में हरित क्षेत्र के संरक्षण में बल्कि लगातार इसके विस्तार में भी सफल रही है। मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सात प्रमुख बड़े शहरों में दिल्ली के पास सबसे बड़ा वन क्षेत्र, लगभग 194.24 वर्ग किलोमीटर का है। दिल्ली का वन और वृक्ष कवर 2019 में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.88 % से बढ़कर 2021 में 23.06 % हो गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में 11 शहरी वन विकसित किए हैं जो तेजी से बढ़ रहे शहरी कंक्रीट निर्माण में एक हरित स्थल का महत्वपूर्ण दायित्व पूरा कर रहे हैं।

115. महोदय, पशुचिकित्सा विज्ञान इस दौर की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि यह न केवल मवेशियों, पालतु पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करता है बल्कि जूनोटिक रोगों की जांच और नियंत्रण से मानव स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। दिल्ली में बड़ी संख्या में पालतू पशु हैं और उनके लिए स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं बजट में हर तरह के पशुओं के बेहतर उपचार के लिए दिल्ली के "पहले सरकारी पशु चिकित्सा महाविद्यालय" की स्थापना के लिए नई स्कीम का प्रस्ताव करता हूं।

116. मैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में पर्यावरण एवं वन क्षेत्र के लिए 266 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं।

परिवहन

117. अध्यक्ष महोदय, 21वीं सदी में अपने किसी काम के लिए अगर नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े तो यह सरकारों के पिछड़ेपन की निशानी है. सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार की निशानी है. केजरीवाल सरकार ने ईमानदार और दूरदर्शी सरकार होने का परिचय देते हुए विभिन्न सरकारी दफ्तरों की सेवाओं को अब तक डोर स्टेप डिलीवरी से जोड़ दिया है। अभी तक 100 तरह की सरकारी सेवाओं के लिए दिल्ली के लोग 4.11 लाख बार इसके तहत अपना काम करा चुके हैं. सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार खत्म करने और आम आदमी को रिश्वतखोरी से बचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की यह क्रांतिकारी योजना भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में तैयार हुई और इसी सदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत पिछले 7 बजट में से एक में यहां पर प्रस्तुत की गई थी. आने वाले साल में डोर स्टेप डिलीवरी की सेवा तीन सौ तरह के सरकारी कार्यों एवं सेवाओं के लिए उपलब्ध होगी

118. लेकिन दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति का सबसे शानदार कदम दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग में उठाया गया है. आजादी के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री ने जाकर ट्रांसपोर्ट विभाग की उस खिड़की को ताला लगाया जिसमें लोगों को लंबी लाइनें लगाकर खड़ा होना पड़ता था. आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उस खिड़की में होने वाले काम को, उस दफ्तर के काम को फेसलेस कर दिया गया. मौजूदा समय में परिवहन विभाग फेसलेस रूप से 47 सेवाओं का संचालन कर रहा है। इस कार्यक्रम से 7 मार्च 2022 तक 11 लाख से अधिक आवेदक लाभान्वित हो चुके हैं।

119. ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, नई गाड़ियों की खरीद के बाद लोगों को अपनी आरसी लेने के लिए सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता था. लेकिन गाड़ी बेचने वाले वाहन विक्रेता को ही सरकार ने गाड़ी की आरसी जारी करने का अधिकार दे दिया है.

120. इसी तरह का एक और प्रोग्रेसिव कदम लर्निंग लाइसेंस बनाने की दिशा में भी उठाया गया है. अब दिल्ली में लर्निंग लाइसेंस बनाने के इच्छुक लोगों को ट्रांसपोर्ट विभाग में नहीं आना पड़ता। चेहरा पहचानने वाले सॉफ्टवेयर की मदद से आम लोग अपना लर्निंग लाइसेंस घर बैठे बनवा रहे हैं। यह भी देश में पहली बार दिल्ली में ही संभव हुआ है।

121. ट्रांसपोर्ट विभाग की एक और उपलब्धि से यहां मैं सदन को अवगत कराना जरूरी समझता हूं, दिल्ली में पहली बार बसों का बेड़ा 7,003 की संख्या पर पहुंचा है. अब तक के दिल्ली के इतिहास में यह सबसे बड़ी बसों की संख्या है.

122. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अक्टूबर 2019 से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध करा रही है। मैं, इस सुविधा को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं और इसके लिए 2022-23 के बजट में 250 करोड़ रुपए आवंटित करता हूं।

123. मैं, 2022-23 के बजट में परिवहन तथा सड़क और पुलों के लिए 9,539 करोड़ रुपए प्रस्तावित करता हूं।

रोड इंफ्रास्ट्रक्चर

124. अध्यक्ष महोदय, सरकार शहर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आश्रम चौक पर अंडरपास का काम पूरा हो चुका है और प्रगति मैदान पर दूसरा अंडरपास मई 2022 तक तैयार हो जाएगा। दिल्ली में पांच पुलों, दो अंडरपास और एक पैदल सब-वे औऱ डीएनडी फ्लाईओवर का आश्रम तक विस्तार का कार्य 2022-23 में पूरा हो जाएगा। इससे त्रिनगर, इंद्रलोक, कर्मपुरा, रामपुरा, नांगलोई, बसई दारापुर, कोंडली और आश्रम चौक से भीड़-भाड़ कम करने में मदद मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं के लिए 2022-23 में 114 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

125. डीएमआरसी करावल नगर, घोंडा और मंगल पांडे मार्ग के बृजपुरी जंक्शन पर एलिवेटेड कॉरिडोर सहित फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कर रही है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है।

126. सरकार दिल्ली के नागरिकों के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 11,000 नि:शुल्क वाईफाई हॉट-स्पॉट स्थापित कर चुकी है। औसतन 4.1 लाख लोग प्रतिदिन इन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

127. महोदय, हमारी सरकार ने आजादी के 75वें वर्ष के समारोहों के अंतर्गत दिल्ली में 500 स्थानों पर भव्य राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई थी। सम्मानित सदन को यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि अब तक दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर 175 राष्ट्रीय ध्वज लगाए जा चुके हैं और शेष ध्वज अगस्त 2022 तक फहरा दिए जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

128. अध्यक्ष महोदय, जब कोविड 19-के दौरान लोगों की नौकरियां गईं और लोगों के व्यापार बंद हुए, लोगों ने अपनों की जान गवाई, परिवारों में कमाने वाला कोविड का शिकार होकर उनको छोड़कर चला गया तो उस दौरान केजरीवाल सरकार एक परिवार की तरह लोगों के साथ खड़ी हुई. एक बड़े भाई की तरह माननीय मुख्यमंत्री ने एक-एक परिवार के दर्द को समझा। दिल्ली पहला ऐसा राज्य था जहां यह योजना बनाई गई कि कोविड-19 के कारण जिस व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है उसके परिवार को तुरंत 50,000 रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए. अब तक 27,322 परिवारों को इस योजना के तहत तुरंत सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है।

129. सिर्फ इतना ही नहीं कोविड के कारण अगर किसी परिवार ने अपने कमाऊ सदस्य का साथ खो दिया है तो दिल्ली सरकार की ओर से उसके आश्रितों को ढाई हजार रुपए प्रतिमाह की पेंशन शुरू की गई है।. यहां यह भी गौरतलब है कि यह पेंशन उस परिवार को मिल रही किसी अन्य पेंशन के ऊपर अलग से दी जा रही है. कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई और इलाज का खर्च सरकार उठा रही है और साथ ही प्रत्येक बच्चे को ढाई हजार रुपे प्रति महीना पेंशन भी दे रही है।

130. महोदय, हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं तथा दिव्यांगजनों और सुविधा वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को लेकर काफी सक्रिय है। इसके तहत 8.50 लाख लाभार्थियों के लिए 2,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये

प्रतिमाह तक की पेंशन दी जा रही है। मैं वर्ष 2022-23 में इन लाभार्थियों के लिए 3,063 करोड़ रूपये की राशि का प्रस्ताव करता हूं।

131. एससी एसटी और गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों के डॉक्टर इंजीनियर या वकील या सिविल सर्विस में जाने के सपने को सच करने के लिए पैसे की कमी ना हो इसके लिए दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है। इसके तहत, करीब 13,136 युवा दिल्ली के सुप्रसिद्ध कोचिंग संस्थानों से अपने कैरियर की परीक्षा की कोचिंग ले रहे हो. वित्तीय वर्ष 2022-23 में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए, मैं इस योजना के तहत 160 करोड रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

132. मैं बजट अनुमान 2022-23 के लिए समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण और खाद्य और नागरिक आपूर्ति के लिए 4,843 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव करता हूं।

श्रम

133. केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में दिल्ली का श्रमिक दिल्ली की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। दिल्ली सरकार ने 2015 में ही श्रमिक का न्यूनतम वेतन देश में सबसे ज्यादा कर दिया था और आज भी यह देश में सबसे ज्यादा है.

134. कोविड की महामारी के दौरान काम और बाजार बंद होने का सबसे ज्यादा असर श्रमिक के ऊपर ही पड़ा है. इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित निर्माण श्रमिक हुए हैं. निर्माण श्रमिकों के दर्द को समझते हुए दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर निर्माण श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन किए और श्रमिकों को सहायता देने की प्रक्रिया को आसान

बनाते हुए करीब 500 करोड रुपए की राशि, 5 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों के खाते में सहायता के रूप में दी।

ऊर्जा

135. आदरणीय महोदय, दिल्ली के नागरिकों को अब चौबीसों घंटे और सातों दिन (24x7) अबाधित बिजली आपूर्ति की जा रही है। 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार की शून्य बिजली बिल योजना बेहद सफल रही है और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में इसका प्रमुख योगदान है। सरकार 1984 के दंगा पीड़ितों को 400 यूनिट तक बिजली की खपत के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी भी देती है। विद्युत सब्सिडी योजना का विस्तार न्यायालय परिसर के भीतर वकीलों के कक्षों तक भी कर दिया गया है। इसी तरह दिल्ली के सभी कृषि उपभोक्ताओं को भी कनेक्शन के लिए सब्सिडी दी जाती है। ये योजनाएं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की स्तंभ पहचान हैं। मैं वर्ष 2022-23 के बजट में बिजली सब्सिडी के लिए 3,250 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

136. माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने भाषण का भाग- ख प्रस्तुत करता हूं जो राजस्व से संबंधित है।

[भाग–ख]

137. माननीय अध्यक्ष महोदय बजट भाषण के पहले भाग में मैंने विस्तार से सरकार की रोजगार और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की नीतियों की चर्चा की है. इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार लगातार अपने संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

138. कोविड महामारी के कारण पिछले वर्ष हमारे कर राजस्व में काफी कमी रही। हालांकि वर्ष 2021-22 के लिए कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में संतोषजनक बढ़ोत्तरी हुई। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान फरवरी 2022 तक हमने 35,112 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया है, इसमें पिछले वर्ष (फरवरी 2021 तक) की तुलना में 39 प्रतिशत की बढोतरी है। ईमानदार प्रशासन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से सतर्कता के चलते सरकार कर चोरी रोकने में सफल रही है।

139. जीएसटी और वैट, सरकार के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत है। वर्ष 2021-22 में (फरवरी 2022 तक) जीएसटी और वैट के लिए कर संग्रह 24,379.03 करोड़ रुपए रहा, जिसमें पिछले वर्ष (फरवरी 2021 तक) की तुलना में 41.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

140. महोदय, हमारी सरकार ने राजस्व बढ़ाने और कर दाताओं की सुविधा के लिए अनेक उपाय किए हैं। हमने हर एक टैक्स वार्ड की, 14 प्रमुख के पी आई पॉइंट्स के साथ, मंथली परफारमेंस मॉनिटरिंग शुरू की है. दिल्ली में कर विभागों में इंस्पेक्टर राज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और सर्वे और स्क्रुटनी के लिए केवल जीएसटी एनालिटिक्स एंड इंटेलीजेंस नेटवर्क (जीएआईएन) का व्यापक तौर पर उपयोग कर रहे हैं। टेक्निक`ल एनालिसिस से मिले सुरागों के आधार पर

अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक 156 सर्वेक्षण किए गए और सरकार को देय 38.76 करोड़ रुपए का पता लगाया गया, जिसमें से 26.57 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। उन करदाताओं के लिए ई-इन्वॉयस भी अनिवार्य किया गया जिनका कुल टर्नओवर 1 अप्रैल 2021 से शुरू वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपए से अधिक था।

141. महोदय, देश में पेट्रोल और डीजल की दरों में, तेल विपणन कंपनियों द्वारा ईंधन का मूल्य बढ़ाने के कारण, तेज बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि आम लोगों के लिए चिंता का विषय है। हमारी सरकार ने नागरिकों को राहत देने के लिए पेट्रोल की बिक्री पर वैट, रुपए में 30 पैसे से कम करके रुपए में 19.40 पैसे कर दिया है।

142. हमारी सरकार ने लोक हित के मुद्दे को जीएसटी परिषद की बैठक में सक्रियता से उठाया है। नए फैसले इस प्रकार हैं-

    a. कोविड-19 के उपचार में काम आने वाली 6 औषधियों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया।
    b. कैंसर की दवा केट्रूदा पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

143. महोदय, हम दिल्ली के व्यापारियों को टैक्स से संबंधित अनावश्यक मुकदमों में उलझने से बचाने के लिए, मुकदमों की संख्या कम से कम करने और लंबित मांगों की वसूली के लिए, जिनमें बकाया कर, ब्याज और जुर्माने की रकम शामिल है, कर माफी योजना लागू करने का प्रस्ताव कर रहे हैं।

144. सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 के जरिये उपभोक्ताओं के अनुभव में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास किया है। पुरानी प्रणाली को आबकारी राजस्व संग्रह की नई प्रणाली से पूरी तरह बदल दिया गया है। इससे प्रतिवर्ष सरकार को कम से कम 4,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

145. नई आबकारी नीति का उद्देश्य सरकार के लिए अधिकतम राजस्व सृजन पक्का करना और दिल्ली में गैर कानूनी और गैर शुल्क भुगतान वाली शराब का उन्मूलन करना है ताकि समग्र व्यापार में कारोबार की आसानी सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक जटिल और अत्यधिक विनियमित आबकारी व्यवस्था को सरल बनाया जा सके।

146. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान राजस्व संग्रह को गति देने के लिए मौजूदा सर्किल दरों में 20 प्रतिशत की छूट की पेशकश की, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक संख्या में सम्पतियों का पंजीकरण हुआ और राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई।

147. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 16.03.2022 तक कुल पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या 2,67,689 है और कुल राजस्व संग्रह 4,680.49 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व संग्रह में पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 27.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

148. सर्किल दरों के पुनरीक्षण के लिए माननीय उप राज्यपाल द्वारा गठित समिति के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सर्किल दरों के संशोधन के व्यापक प्रक्रिया जारी है।

149. अध्यक्ष महोदय अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आज मैंने अगले वित्त वर्ष के लिए जो योजनाएं और बजट प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रखे हैं, उसमें दिल्ली के गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए अपार संभावनाएं हैं. सरकार अपने प्रयासों से और प्राइवेट सेक्टर के साथ अच्छी नियत की पार्टनरशिप करके दिल्ली की तरक्की को सुनिश्चित करेगी और दिल्ली वासियों के लिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता से रोजगार पैदा करने के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी।

150. जिस तरह पिछले 7 साल में दिल्ली में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी आदि के काम का दिल्ली वालों को फायदा मिला है और पूरे देश की राज्य सरकारों ने, यहां तक कि विपक्ष की राज्य सरकारों ने भी दिल्ली से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है. वह चाहे मोहल्ला क्लीनिक हो, मुफ्त बिजली और पानी की स्कीम हो, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प और हैप्पीनेस जैसे पाठ्यक्रम हो, डोर स्टेप डिलीवरी की योजना हो... ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने की और राज्य सरकारों ने उससे कुछ सीखा या उस जैसा कुछ करने की कोशिश की।

151. मुझे पूरा यकीन है आज सदन में प्रस्तुत रोजगार बजट का सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली के लोगों को मिलेगा जहां लोगों के लिए नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे. और मुझे यह भी पूरा यकीन है कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर अंदर सारी राज्य सरकारें दिल्ली के इस मॉडल को भी समझने की कोशिश करेंगी की सरकार और प्राइवेट सेक्टर जब एक साथ मिलकर राज्य की ग्रोथ के लिए काम करते हैं तो नौकरियों के और रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा हो सकते हैं. केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नर्स से देश ने सीखा है कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक हो सकते हैं, 24 घंटे मुफ्त बिजली कैसे दी जा सकती है, आने वाले समय में पूरा

देश केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट से यह भी सीखेगा की ठीक से योजनाएं बनाकर एक बड़ी आबादी को रोजगार कैसे दिया जा सकता है.

दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य-प्रकाश तुम्हारा,
लिखा जा चुका अनल-अक्षरों में इतिहास तुम्हारा।
जिस मिट्टी ने लहू पिया, वह फूल खिलाएगी ही,
अम्बर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा।
और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है।
वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है
थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है
थककर बैठ गये क्या भाई! मंज़िल दूर नहीं है।
-रामधारी सिंह दिनकर